[2019] 15 एस. सी. आर.

डॉ. (मेजर) मीता सहाय

बनाम्

बिहार राज्य और अन्य

(दीवानी अपील संख्या 9482/2019)

17 दिसंबर, 2019

[दीपक गुप्ता और सूर्या कांत, न्यायमूर्तिगण]

सेवा कानूनः

बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2013-rr.2 (ए), 5 और 6 (iii)-राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन - यह अनिवार्य करते हुए कि 'कार्य अनुभव' के लिए अंक देने के लिए केवल राज्य सरकार के अस्पतालों में कार्य अनुभव पर विचार किया जाना था-सैन्य अस्पताल में अपीलार्थी के कार्य अनुभव पर विचार नहीं किया गया था-विज्ञापन में इस तरह के खंड को चुनौती देने वाली रिट याचिका नियम 5 और 6 को विपरीत मनमाना और प्रतिकुल है ।(iii)-रिट याचिका को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था-रिट अपील को भी उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था-सर्वोच्च न्यायालय में अपील- अभिनिर्धारितनियम 5 और 6 (iii) को शाब्दिक व्याख्या के सिद्धांत को लागू करके नहीं समझा जा सकता है-'सरकारी अस्पताल' अभिव्यक्ति का अर्थ 'सरकार' की परिभाषा को धारा 2 (क) में आयात करके नहीं किया जा सकता है। नियमों के निर्माण के पीछे राज्य में अस्पतालों की अनूठी चुनौती को पहचानना और डॉक्टरों को गैर-निजी अस्पतालों में काम करने

के लिए प्रोत्साहित करना था-राज्य सरकार और केंद्र सरकार या नगरपालिकाएँ पंचायती राज संस्थान द्वारा संचालित अस्पतालों के बीच भेदभाव करने का कोई भी प्रयास या पंचायती राज संवैधानिक शासन के मूल्यों को प्रभावित करने के लिए बाध्य हैं-इसलिए, नियम 5 और 6 (iii) का अर्थ राज्य सरकार या उसके उपकरणों द्वारा संचालित किसी भी अस्पताल के साथ-साथ केंद्र सरकार, नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थानों या राज्य के क्षेत्र के भीतर अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा संचालित किसी अन्य गैर-निजी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा प्राप्त अनुभव को शामिल करना है।

अवरोध

चयन प्रक्रिया को चुनौती-असफल होने के बाद, इस तरह की प्रक्रिया से गुजरना-चाहे रोक दिया गया हो-अभिनिर्धारित विबंधन का सिद्धांत एक उम्मीदवार को इसमें विफल होने के बाद चयन प्रक्रिया को चुनौती देने से रोकता है-हालाँकि, इस सिद्धांत को अलग किया जाता है क्योंकि उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सहमत होकर केवल निर्धारित प्रक्रिया को स्वीकार करता है न कि इसमें अवैधता को यदि चुनौती वैधानिक नियमों के गलत निर्माण और उससे उत्पन्न होने वाले भेदभावपूर्ण परिणामों का आरोप लगाती है, तो इसे केवल इसलिए माफ नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक उम्मीदवार ने इसमें भाग लिया है-इसके अलावा, जब तक कि उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है, तब तक प्रावधानों की अवैधता या अपमान पर हमला करने का अधिकार नहीं हो सकता है।

क़ानूनों की व्याख्याः

वैधानिक प्रावधान का निर्माण-अभिनिर्धारित पहले कदम के रूप में न्यायालयों को प्रावधानों के विषय वस्क की व्याख्या करनी चाहिए और इसका शाब्दिक रूप से निर्माण करना चाहिए-व्याख्या का यह साधन केवल तभी लागू किया जा सकता है जब अधिनियम के विषय वस्क केवल एक ही अर्थ के लिए संवेदनशील हो-जहां पाठ के अर्थ में अस्पष्टता है, न्यायालयों को ऐसी कमी को दूर करने के लिए परिणामों पर भी

उचित ध्यान देना चाहिए-जब दो प्रशंसनीय व्याख्याएं हो, तो संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाले को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अपील को स्वीकृति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1.1 अवरोध का सिद्धांत एक उम्मीदवार को इसमें विफल होने के बाद चयन प्रक्रिया को चुनौती देने से रोकता है। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य उम्मीदवार को एक और प्रयास करने का विचार से रोकना है। और एक ऐसे गतिरोध से बचना है जिसमें प्रत्येक असंतुष्ट उम्मीदवार, चयन में विफल होने के बाद, दूसरा मौका मिलने की उम्मीद में इसे चुनौती देता है। [कंडिका 17] [287-एफ; 288-बी-सी]

1.2 हालांकि, इस सिद्धांत को अलग किया जाता है क्योंकि उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सहमत होकर केवल निर्धारित प्रक्रिया को स्वीकार करता है न कि इसमें अवैधता को। ऐसी स्थिति में जहां एक उम्मीदवार वैधानिक नियमों के गलत निर्माण और उससे उत्पन्न होने वाले भेदभावपूर्ण परिणामों का आरोप लगाता है, उसे केवल इसलिए माफ नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसने इसमें भाग लिया है। संवैधानिक योजना पवित्र है और किसी भी तरह से इसका उल्लंघन अस्वीकार्य है। वास्तव में, एक उम्मीदवार को संविधान के प्रावधानों की लाइलाज अवैधता या अपमान पर हमला करने का अधिकार नहीं हो सकता है, जब तक कि वह चयन प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। [कंडिका 18] [288-सी-डी]

1.3 अपीलार्थी ने चयन प्रक्रिया को उचित रूप से चुनौती नहीं दी है, लेकिन योग्यता निर्धारण के हिस्से रुप में कार्य अनुभव की उत्तरदाताओं की व्याख्या के खिलाफ अपने चयन प्रक्रिया के दावे को सीमित कर दिया है। चूँकि किसी क़ानून या नियम की व्याख्या न्यायालयों का अनन्य क्षेत्र है, और ऐसे मानदंडों को रेखांकित करने में न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश को देखते हुए, अपीलार्थी की चुनौती को सीमा पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। [कंडिका 20] [289-ए-बी]

मनीष कुमार शाही बनाम बिहार राज्य (2010) 12 एस. सी. सी. 576-पर निर्भर किया गया।

2.1 यह वैधानिक व्याख्या की एक निश्चित सिद्धांत है कि पहले कदम के रूप में, न्यायालयों को प्रावधान के विषय वस्क की व्याख्या करनी चाहिए। इसका प्रावधान करें और इसका अक्षरथ: से निर्माण करे।कानून के प्रावधानों को उनके मूल व्याकरणिक अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए ताकि इसके शब्दों को एक सामान्य पाठ्य अर्थ दिया जा सके। तथापि, व्याख्या के इस उपकरण को केवल उन मामलों में लागू किया जा सकता है जहां अधिनियम के विषय वस्तु केवल एक अर्थ के लिए संवेदनशील हो। फिर भी, ऐसी स्थिति में जहां विषय वस्तु के अर्थ में अस्पष्टता हो, न्यायालयों को इसके व्याख्या के परिणामों को भी ध्यान में रखना चाहिए। [कंडिका 21] [289-सी-डी]

नाथी देवी बनाम राधा देवी गुप्ता (2005) 2 एस. सी. सी. 271: [2004] 6 पूरक एस. सी. आर. 1141-पर निर्भर।

2.2 यह न्यायालयों की जिम्मेदारी है कि वे पाठ की व्याख्या इस तरह से करें जिससे कठिनाई असुविधा, अन्याय, मूर्खता या विसंगति किसी भी तत्व को समाप्त किया जा सके। एक कानून को अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाना चाहिए और प्रणाली में कोई भ्रम या टकराव पैदा नहीं करना चाहिए। यदि इस तरह के कानून के पाठ का सामान्य अर्थ प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के लिए अनुकूल नहीं है, तो इस तरह की कमी को दूर करने के लिए इसकी व्याख्या तदनुसार की जानी चाहिए। [कंडिका 22] [289-ई]

मदन लाल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (1995) 3 एस. सी. सी. 486:[1995] 1 एस. सी. आर. 908-पर निर्भर था।

जी. पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत (14 वां संस्करण, 2016) पी.पी 145-170-संदर्भित।

2.3 इसमें कोई संदेह नहीं है कि कार्यपालिका के कार्य जैसे विज्ञापन न तो कानूनों के दायरे या उद्देश्य का विस्तार कर सकते हैं और न ही उन्हें प्रतिबंधित कर

सकते हैं।इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि 'सरकारी अस्पताल' वाक्यांश की व्याख्या नियमों में दिखाई देती है। [कंडिका 23] [289-एफ]

2.4 बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम 2013 का नियम 2 एक परिभाषित प्रावधान है और 'सरकार' को एक संज्ञा के रूप में परिभाषित करता है। हालांकि ऐसा नहीं होगा। यह आवश्यक रूप से उन उदाहरणों को नियंत्रित नहीं करेगा जहां शब्द का उपयोग अन्य रूप में किया गया है। नियम 5 के तहत, ऑपरेटिव वाक्यांश "कोई भी सरकारी अस्पताल" है।यहाँ, 'सरकार' कुछ संस्थाओं द्वारा संचालित लोगों को बाहर करने के लिए 'अस्पताल' संज्ञा को प्रतिबंधित रूप से परिभाषित कर रही है।इस प्रकार, 'सरकारी अस्पताल' के हिस्से के रूप में 'सरकार' एक संज्ञा सहायक है और इसका उपयोग एक विशेषण के रूप में किया गया है।किसी संज्ञा का उसके विशेषण रूप में इस तरह का उपयोग उसके चरित्र को पूरी तरह से बदल देता है और उसके संज्ञा रूप के अर्थ को आयात करना मूर्खतापूर्ण होगा।यह विशेष रूप से इस बात पर विचार करते हुए सही है कि कैसे नियम 2 के प्रारंभिक भाग में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि इसके तहत निर्धारित परिभाषाओं को तब तक संदर्भित किया जाएगा जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो। इसलिए 'सरकारी अस्पताल' वाक्यांश को अन्य गैर-निजी अस्पतालों को बाहर करने के लिए नहीं माना जा सकता है जो अन्यथा विशेष रूप से सरकारों की सहायता और सहायता से चलाए जाते हैं।इसके अतिरिक्त सामान्य उपयोग में अंतर को देखते हुए जिसमें 'सरकारी अस्पताल' सभी गैर-निजी अस्पतालों को संदर्भित करता है न कि किसी विशेष सरकार द्वारा स्थापित अस्पतालों को। नियम 5 और 6 (iii) नियम 2 (ए) से बाध्य नहीं होंगे। [कंडिका 24] [290-सी-एफ]

नवीनचंद्र मफतलाल बनाम सी. आई. टी., [1955] 1 एस. सी. आर. 829-पर निर्भर था।

एफसीसी बनाम एटी और टी इंक. 562 यू. एस. 397 (2011)-संदर्भित।

2.5 नियम 5 में 'कोई भी' शब्द की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण है।यह एक व्यापक अर्थ प्रदान करने के लिए एक विधायी इरादे को कार्य अनुभव अर्जित करने के लिए अस्पताल की योग्यता को इंगित करता है। नियम 2 (ए) की प्रतिबंधात्मक परिभाषा का आयात करने से एक ही अंतर्निहित संज्ञा पर लागू होने वाले विस्तृत और प्रतिबंधात्मक दोनों विशेषणों को लागू करने में एक विषय स्थिति पेदा हो सकती है। नतीजतन, न्यायालय इस वाक्यांश की एक विस्तृत व्याख्या को अपनाने के लिए इच्छुक है, और नियम 2 (ए) पर भार नहीं डालता है। [कंडिका 25] [290-जी; 291-ए]

2.6 इसके अतिरिक्त प्रतिवादी की व्याख्या को अपनाने से अनिश्चितता बढ़ेगी और व्यावहारिक कठिनाईयाँ पैदा होंगी। जब नियम 2 (ए) को 'सरकारी अस्पताल' पर लागू किया जाता है तो इस बारे में पर्याप्त अस्पष्टता पैदा होती है कि सरकार के उपकरणों द्वारा संचालित अस्पताल, जो पूरी तरह से बिहार सरकार के स्वामित्व में नहीं हैं, उन्हें नियम 5 में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इस तरह के मुद्दे किसी भी चयन प्रक्रिया में बार-बार उठना तय है। यह देखते हुए कि ऐसे प्रश्नों का कोई सरल उत्तर नहीं है, सरकार द्वारा अपनाई गई कठोर व्याख्या, प्रणाली में टकराव पैदा करेगी और व्याख्यात्मक अराजकता का कारण बनेगी जो सार्वजनिक रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा करने के स्पष्ट और उचित अधिकार को कमजोर करेगी। [कंडिका 26] [291-बी-डी]

2.7 इसके अलावा, यदि एक ऐसे विकल्प का सामना करना पड़ता है जिसमें केवल कुछ लोग पात्र होंगे बनाम काफी बड़ा समूह होगा तो बाद वाले को विभिन्न प्रकार के आवेदकों के समूह के लिए अपनाया जाना चाहिए।यह योग्यता को बढ़ावा देगा, बेहतर डॉक्टर लाएगा और जनता को सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर प्रदान करने की संवैधानिक योजना को आगे बढ़ाएगा ।इस प्रकार, वर्तमान मामले में नियमों के प्रावधानों को शाब्दिक व्याख्या के सिद्धांत पर लागू करके समझा या समझाया नहीं जा सकता है। [कंडिका 27] [291-ई]

2.8 इसलिए, अपने उद्देश्यों के आलोक में नियमों के प्रावधानों की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या का सहारा लेना आवश्यक है। अन्यथा संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रारंभिक भाग के अनुसार, इसके तहत बनाए गए नियम अन्य सभी संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होने चाहिए, जिसमें अनिवार्य रूप से भाग III शामिल है। सरकारी अस्पतालों में भर्ती से संबंधित स्पष्ट है कि नियमों का उद्देश्य और उद्देश्य भी अनुच्छेद 16 की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। [कंडिका 28] [291-एफ-जी]

2.9 इसके अलावा, नियमों के तहत 'सरकारी अस्पतालों' की स्पष्ट परिभाषा के अभाव को देखते हुए, न्यायालय वैधानिक व्याख्या के साधन के रूप में संवैधानिक मूल्यों का उपयोग करना उचित समझता है। संविधान को न केवल विधानों की वैधता के परीक्षण के लिए एक बेंचमार्क के रूप मे देखा जाना चाहिए, बल्कि राज्य की कठिनाई का मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रेरणादायक दस्तावेज के रूप में भी देखा जाना चाहिए। विधानों की वैधता का परीक्षण करने के लिए मानक, लेकिन राज्य की कार्रवाई का मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रेरणादायक दस्तावेज के रूप में भी। जब दो प्रशंसनीय व्याख्याएँ होती हैं, तो संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली व्याख्या को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। [कंडिका 29] [291-एच; 292-ए-बी]

आर बनाम जार्विस, 2019 एस. सी. सी. 10-पर भरोसा किया।

2.10 संवैधानिक योजना के तहत दायित्व और 'राज्य' के कर्तव्यों को तीन स्तरीय शासन प्रणाली का उपयोग करके स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है।राष्ट्रीय स्तर पर भारत संघ, राज्य स्तर पर राज्य सरकारें और स्थानीय स्तर पर अलग-अलग विभिन्न नगरपालिकाएं/पंचायतें, समानांतर रूप से आम जनता के कल्याण के लिए अपने-अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करती हैं। संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत अपने लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने, पर्याप्त पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्यों का सम्मान करते हुए, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाती हैं और अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित संस्थानों की स्थापना करती हैं।इसके अलावा, संविधान की अनुसूची XI की प्रविष्टि 23 के साथ पठित अनुच्छेद 243G के तहत, राज्य का विधानमंडल,

पंचायती राज संस्थानों को "अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और औषधालयों सहित स्वास्थ्य और स्वच्छता" के कार्य सौंप सकता है।इसी तरह, राज्य विधानमंडल अनुसूची बारहवीं की प्रविष्टि 6 के साथ पठित अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के तहत नगर पालिकाओं को "सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन" के कार्य सौंप सकता है।इन स्थानीय सरकारों के अस्पताल अक्सर राज्यों के समेकित कोष से प्राप्त धन के आधार पर चलाए जाते हैं।इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि संविधान में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिकाएँ और पंचायती राज संस्थान सहित कई अलग-अलग सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अस्पतालों की स्थापना की परिकल्पना की गई है। [कंडिका 30,31] [292-बी-एफ]

2.11 इसके अलावा, केंद्र या राज्य सरकारों, विशेष रूप से कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों की सहायता से देश भर में कई अस्पतालों की स्थापना की गई है, ताकि गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा किया जा सके।इसलिए ये अस्पताल सभी नीयत और उद्देश्यों के लिए अन्य सरकारी अस्पतालों के बराबर हैं, और ऐसे अस्पतालों में एक डॉक्टर द्वारा प्राप्त अनुभव बिहार सरकार द्वारा स्थापित अस्पताल में प्राप्त विशेषताओं को समाहित करता है। [कंडिका 32] [292-जी; 293-ए]

2.12 अन्य अस्पताल भी भाग IV के तहत संवैधानिक दायित्वों के अनुसरण में राज्यों और केन्द्र के साधन से स्थापित किए गए है। यद्यपि ये उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तावित नियमों के दायरे में सख्ती से शामिल नहीं हैं, फिर भी वे बड़े पैमाने पर जनता को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के समान उद्येश्य को पूरा करते है। एक उपयुक्त उदाहरण सेना के अस्पतालों का है, करने का बहुत कम कारण है। ऐसे अस्पतालों में प्राप्त अनुभव को नजरअंदाज करें।[कंडिका 33] [293-बी]

2.13 इसलिए यह आग्रह करना अतार्किक है कि ऐसे किसी भी अस्पताल में कार्य अनुभव बिहार के सरकारी अस्पताल से अलग है। इसलिए, पंचायतों या नगर पालिकाओं द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित इन अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा प्राप्त अनुभव और बिहार के क्षेत्र में इसके उपकरणों और बिहार सरकार द्वारा संचालित

अस्पतालों के बीच अंतर की अनुमति देना संवैधानिक रूप से अन्यायपूर्ण होगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार या नगर पालिकाओं/पंचायती राज संस्थानों द्वारा संचालित अस्पतालों के बीच भेदभाव करने का कोई भी प्रयास संवैधानिक शासन व्यवस्था के लोकाचार को प्रभावित करने के लिए बाध्य है। [कंडिका 34] [293-सी-डी] बी

2.14 ऐसा कहने के बाद, न्यायालय इस तथ्य से अनजान नहीं है कि समानता का अर्थ यह नहीं है कि कोई वर्गीकरण नहीं हो सकता है। इसके बजाय, कभी-कभी यह आवश्यक हो जाता है कि असमान लोगों के साथ व्यवहार असमान रूप से, असमान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार के लिए परिस्थितियाँ अन्यायपूर्ण स्थिति पैदा करती हैं। हालाँकि, इस तरह का वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि तर्कसंगत रूप से कुछ गुणवत्ता या विशेषताओं पर आधारित होना चाहिए जो इस तरह से बनाए गए लोगों के वर्ग के भीतर पहचान योग्य हैं और इस तरह के वर्गीकरण से बाहर रखे गए लोगों में अनुपस्थित हैं। [कंडिका 35] [293-ई] डी

> इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ (1992) पूरक।3 एस. सी. सी 217:[1992] 2 पूरक एस. सी. आर. 454-अनुसरण किया गया।

2.15 नियमों के निर्माण के पीछे का उद्देश्य बिहार के अस्पतालों की अनूठी चुनौतियों को पहचानना था और गैर-निजी अस्पतालों में काम करने के लिए डॉक्टरों को प्रोत्साहित करना। गैर-निजी अस्पताल में अनुभव उसके डॉक्टरों में संवेदनशीलता पैदा करता है, जिससे वे गरीब रोगियों की बीमारी और पीड़ा को समझने में अधिक निपुण हो जाते हैं। इस तरह का अनुभव निस्संदेह सरकारी अस्पतालों के उद्देश्य को आगे बढ़ाना और उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करते समय उन्हें उचित महत्व देने में उपयोग होगा। बिहार सरकार के तहत काम करने वाले व्यक्तियों के केवल एक छोटे से वर्ग को शामिल करने के लिए 'सरकारी अस्पतालों' की व्याख्या करना स्पष्ट रूप से गलत और योग्यता विरोधी है। ऐसा उद्देश्य नियमों की समझ से पराजित नहीं होगा, जैसा कि अर्थ लगाया गया है। [कंडिका 36] [293-एफ-जी; 294-ए-बी]

2.16 अतः बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2013 के नियम 5 और 6 (iii) में बिहार सरकार या उसके उपकरणों द्वारा संचालित किसी भी अस्पताल के साथ-साथ बिहार के क्षेत्र के भीतर किसी अन्य गैर-निजी अस्पताल (केंद्र सरकार, नगर पालिकाओं और पंचायती राज संस्थानों या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा संचालित अस्पतालों सहित) में एक डॉक्टर द्वारा प्राप्त अनुभव को शामिल माना जाता है। तदनुसार उत्तरदाताओं को फिर से काम करने और उन्हें अपीलार्थी और इसी तरह के अन्य उम्मीदवार को उचित महत्व देकर एक नई योग्यता सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। [कंडिका 37] [294-सी-डी]

डॉ. धर्मबीर कुमार बनाम बिहार राज्य (2015) 2 पीएलजेआर 916; राम सूरत मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। (2008) 7 एस. सी. सी. 409; मेसर्स जे. के. जूट मिल्स कं. लिमिटेड बनामउत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1534 [1962] एस. सी. आर. 1-निर्दिष्ट।

मामला कानून संदर्भ

(2015) 2 पीएलजेआर 916	कंडिका 6 को	संदर्भित किया गया
(2008) 7 एससीसी 409	कंडिका 8 को	संदर्भित किया गया
[1962] एससीआर 1	कंडिका 8 को	संदर्भित किया गया
(2010) 12 एससीसी 576	कंडिका 17 पर	उस पर भरोसा करें
[2009] 5 एससीआर 89	कंडिका 21 पर	उस पर भरोसा करें
[2004] 1 पूरक एससीआर 668	कंडिका 22 पर	उस पर भरोसा करें
[2004] 6 पूरक एससीआर 1141	कंडिका 22 को	संदर्भित किया गया
[1955] 1 एससीआर 829	कंडिका 24 पर	भरोसा करें

562 यू. एस. 397 (2011)	कंडिका 24 को	संदर्भित किया गया
(2019) एस. सी. सी. 10	कंडिका 20 पर	भरोसा करें
[1992] 2 पूरक एससीआर 454	कंडिका 35 पर	पीछा किया।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 की दीवानी अपील संख्या 9482।

2016 के एल. पी. ए. सं. 1860 में पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और आदेश दिनांक 24.11.2016 से।

गौरव अग्रवाल, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

शिवम सिंह, गुरप्रीत सिंह गुप्ता, गोपाल सिंह, नवीन प्रकाश, अधिवक्ता उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय सूर्य कांत, न्यायमूर्ति

निर्णय

अनुमति दी गई।

2. वर्तमान अपील पटना उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा दिनांक 24.11.2016 को एलपीए संख्या 1860/2016 में पारित किए गए आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें सेना अस्पताल में अपीलकर्ता के कार्य अनुभव पर भारांक प्रदान करने और परिणामी चयन और बिहार राज्य में सामान्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया गया था, उस आधार पर कि बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2013 (इसके बाद, 'नियम') के नियम 6 (iii) के अनुसार केवल बिहार सरकार द्वारा संचालित एक अस्पताल के नियोजन में प्रदान की गई सेवाओं की गणना कार्य अनुभव के शीर्ष के तहत की जा सकती है।

वास्तविक उद्गम-स्थल

3. सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे बिहार में डॉक्टरों की लगातार कमी को दूर करने के लिए, प्रत्यक्षतः बिहार राज्य ने अस्पतालों में रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया।तदनुसार, बिहार लोक सेवा आयोग (इसके बाद आयोग) द्वारा 18.07.2014 को विभिन्न स्थानीय समाचार पत्रों में बिहार में जनरल मेडिकल ऑफिसर के 2301 रिक्त पदों को भरने के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे।चयन प्रक्रिया को विज्ञापन के खंड 5 में स्पष्ट किया गया था, जिसमें सामान्य उप-कैडर के डॉक्टरों का चयन शैक्षणिक योग्यता (एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्राप्त अंक 50 अंक और उच्च डिग्री पाठ्यक्रम में 10 अंक), कार्य अनुभव (अधिकतम 25 अंक के लिए प्रति वर्ष 5 अंक) और साक्षात्कार में प्राप्त अंक (15 अंकों में से) के लिए वेटेज देकर तैयार की गई योग्यता सूची के आधार पर किया जाना था।चयन मानदंडों को उचित रूप से समझने के लिए विज्ञापन के प्रासंगिक हिस्से को पुनः प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैः

> "5. चयन प्रक्रिया-सामान्य उप-संवर्ग में डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव के आधार पर तैयार की गई मेधा सूची और साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर किया जाएगा।रिक्तियों/रिक्तियों से अधिक आवेदन होने की स्थिति में, निर्धारित आरक्षण के अनुसार रिक्तियों/रिक्तियों की तुलना में पांच गुना उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
>
> शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव और साक्षात्कार के लिए 100 अंक निर्धारित किए जाएंगे।100 अंकों की गणना निम्नानुसार की जाएगी,
>
> एम बी बी एस में प्राप्त किये गए अंक-कुल 50 अंक
>
> मास्टर डिग्री या उच्चतर डिग्री-कुल 10 अंक

सरकारी अस्पतालों में नियमित/अनुबंध आधार पर नियुक्ति के बाद कार्य अनुभव (केवल बिहार सरकार के सरकारी अस्पताल के कार्य अनुभव को ही गिना जाएगा)-कुल 25 अंक लेकिन पूरे वर्ष के कार्य अनुभव के लिए 05 अंक दिए जाएंगे, इस प्रकार अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे।

मौखिक साक्षात्कार-कुल 15 अंक

नोट-(ए) एमबीबीएस पाठ्यक्रम के आधार पर किसी भी उम्मीदवार को दिए गए अंक उक्त पाठ्यक्रम की सभी परीक्षाओं की कुल संख्या के साथ 0.5 के गुणन पर होंगे।यदि किसी उम्मीदवार द्वारा एमबीबीएस की सभी परीक्षाओं में प्राप्त कुल अंकों में से 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए जाते हैं, तो उसे 50 प्रतिशत x 0.5 = 25 अंक दिए जाएंगे।

(ख) (sic) (c) सामान्य ड्यूटी सब-कैडर में नियुक्ति के लिए किसी भी उम्मीदवार के विचार के लिए शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव और साक्षात्कार के आधार पर न्यूनतम 30 अंकों की आवश्यकता होगी।"

(जोर दिया गया)

4. इस विज्ञापन के अनुसरण में, अपीलार्थी ने सामान्य चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए भी आवेदन किया.उन्हें एक साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, जहां उन्हें बताया गया कि बिहार सरकार द्वारा संचालित एक अस्पताल में उनके पास अनुभव की कमी के कारण 'कार्य अनुभव' के शीर्ष के तहत कोई अंक नहीं दिए जा सकते हैं। साक्षात्कार के बाद एक मेधा सूची तैयार की गई। अपीलार्थी योग्यता सूची में स्थान पाने में असफल थी क्योंकि उसने केवल 42.61 अंक प्राप्त किए थे जो सामान्य श्रेणी के लिए 53.04 अंकों के निर्धारित कट ऑफ को पूरा नहीं करते थे।

5. व्यथित अपीलार्थी ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष आयोग द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के खंड 5 (iii) को उस सीमा तक चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की, जिसमें आयोग ने यह अधिदेश दिया था कि केवल बिहार सरकार के अस्पतालों में कार्य अनुभव के लिए अंक देने पर विचार किया जाएगा। अपीलार्थी ने तर्क दिया कि विज्ञापन का यह खंड नियमों के उल्लंघन में था (जिसमें केवल बिहार सरकार के अस्पतालों में होने के कारण कार्य अनुभव की ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई थी)। वह इस बात से नाराज थीं कि सेना के मेडिकल कॉर्प अस्पताल में उनके कार्य अनुभव की उपेक्षा की गई जबकि बिहार के सरकारी अस्पतालों में सेवा देने वाले अन्य लोगों को उचित महत्व दिया गया।उन्होंने महसूस किया कि यदि नियमों की ऐसी गलत व्याख्या न होती तो उन्हें जनरल मेडिकल ऑफिसर के पद के लिए चुन लिया गया होता। इसी प्रकार, कुछ अन्य उम्मीदवारों ने भी पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और बिहार सरकार द्वारा प्रशासित अस्पतालों के अलावा गैर-मामूली निजी अस्पतालों में कार्य अनुभव पर विचार नहीं करते हुए अपना बहिष्कार करने का विरोध किया।

6. उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक संक्षिप्त आदेश के साथ इन सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि इस तरह के प्रावधान की वैधता को पहले ही पटना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा डॉ. धर्मबीर कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में अनुमोदित किया जा चुका था, 1 और, इसलिए, अपीलार्थी यह दलील नहीं दे सकता था कि कार्य अनुभव का मूल्यांकन करते समय सेना के अस्पतालों में प्रदान की जाने वाली सेवा को अपवर्जित करने से भेदभाव हुआ।

7. इस आदेश से असंतुष्ट होकर, अपीलार्थी ने इस सर्वप्रथम दलील के साथ एक लेटर पेटेंट अपील दायर की कि विज्ञापन की वह शर्त, जिसने केवल बिहार सरकार के अस्पतालों तक कार्य अनुभव को सीमित कर दिया था, उन नियमों के विपरीत थी जो योग्यता सूची तैयार करने के उद्देश्य से किसी भी सरकारी अस्पताल में अनुभव को महत्व देते थे। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि धर्मबीर (उपर्युक्त) में

खंडपीठ ने दंत चिकित्सकों की नियुक्ति से संबंधित एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें संविदा कर्मचारियों को अनुभव का लाभ प्रदान करने के खिलाफ एक चुनौती दी गई थी। इसका प्रतिवाद वर्तमान मामले से भिन्न होने के रूप में किया गया था.इसके अलावा, अपीलकर्ता ने बिहार दंत चिकित्सक सेवा नियमावली, 2014 के अंग्रेजी संस्करण पर भरोसा किया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा संचालित अस्पतालों को शामिल करने के लिए 'सरकारी अस्पताल' शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, यह दिखाने के लिए कि इसे वर्तमान उदाहरण में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

8. खंडपीठ ने इस न्यायालय के कई निर्णयों पर भरोसा किया जिसमें राम सूरत मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और मैसर्स जे के जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सम्मिलित है, और यह नोट करने के लिए अनुशरण किया कि कैसे हिंदी संस्करण केवल बिहार सरकार को संदर्भित करता है और अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों के बीच संघर्ष होने पर बिहार दंत चिकित्सक सेवा नियम, 2014 का उत्तरवर्ती संस्करण प्रबल होगा।पीठ ने आगे कहा कि दंत चिकित्सक नियमों के नियम 2 (ए) में सरकार को बिहार सरकार के रूप में परिभाषित किया गया है और इस प्रकार नियम 6 (iii) के तहत कार्य अनुभव को नियम 2 (ए) के साथ संयुक्त रूप से पढ़ा जाना चाहिए जो यह दर्शाता है कि कार्य अनुभव के शीर्ष के तहत अंक देने के लिए बिहार सरकार के अस्पतालों में केवल कार्य अनुभव पर विचार किया जाना चाहिए।इस प्रकार अंतः न्यायालय अपील को खारिज कर दिया गया, जिससे इस विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से आगे चुनौती को बढ़ावा मिला।

<u>पी आर्टीज का आरंभ</u>

9. अपीलार्थी के विद्वत वकील ने जोरदार तर्क दिया कि खंडपीठ का निर्णय गलत था।उन्होंने विज्ञापन के खंड 5 (iii) की आलोचना की और आग्रह किया कि केवल बिहार सरकार के अस्पतालों के लिए कार्य अनुभव पर प्रतिबंध मनमाना और नियमों के नियम 5 और नियम 6 (iii) के विपरीत है, जो इस प्रकार हैः

“5. सामान्य सेवा उप संवर्ग में नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस डिग्री होगीः

बशर्ते कि चिकित्सा विज्ञान के किसी भी विषय में स्नातकोत्तर या उच्च डिग्री धारक और किसी भी सरकारी अस्पताल में नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्त डॉक्टरों को कार्य अनुभव के लिए वेटेज दिया जाएगा।

6. सामान्य उप संवर्ग में नियुक्ति के लिए डॉक्टरों के चयन के लिए, उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव के लिए भी अंक दिए जाएंगे।इसके अलावा, उन्हें मौखिक साक्षात्कार के लिए अंक भी दिए जाएंगे।

कुल 100 अंक शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव और साक्षात्कार के लिए होंगे।इन 100 अंकों का विवरण इस प्रकार होगाः

(i) एमबीबीएस में प्राप्त अंक कुल 50 अंक

(ii) स्नातकोत्तर या उच्चतर डिग्री कुल 10 अंक

(iii) सरकारी अस्पतालों में अनुबंध/नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद कार्य का अनुभव-कुल 25 अंक

बशर्ते कि प्रत्येक पूरे एक वर्ष के कार्य अनुभव के लिए उम्मीदवारों को 5 अंक दिए जाएंगे और इस प्रकार अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे।

साक्षात्कारः कुल 15 अंक

नोटः (क) एमबीबीएस के लिए उम्मीदवार को दिए जाने वाले अंकों का निर्धारण उक्त पाठ्यक्रम की परीक्षा में प्राप्त अंकों के कुल

प्रतिशत के 0.5 के गुणज में किया जाएगा।इस प्रकार, यदि किसी उम्मीदवार ने 50% अंक प्राप्त किए हैं, तो उसे 50 x 0.5 = 25 अंक मिलेंगे

(ख) सामान्य उप-संवर्ग और विशेषज्ञ उप-संवर्ग में नियुक्ति के लिए न्यूनतम 30 अंकों की आवश्यकता होगी।"

(जोर दिया गया)

10. उन्होंने तर्क दिया कि नियमों में 'सरकारी अस्पताल' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है और इसलिए इसका सामान्य अर्थ लिया जाना चाहिए।चूंकि ये नियम संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए हैं, इसलिए आयोग या राज्य सरकार किसी भी सरकारी अस्पताल को केवल विज्ञापन के माध्यम से बिहार सरकार के सरकारी अस्पताल तक सीमित नहीं कर सकती थी। यह भी तर्क दिया गया कि बिहार के सरकारी अस्पतालों से परे प्रदान की जाने वाली सेवाओं का बहिष्कार भेदभावपूर्ण होगा क्योंकि यह बेहतर योग्य डॉक्टरों की भर्ती को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में प्राप्त तकनीकी ज्ञान या विशेषज्ञता को मान्यता देने के लिए नियमों के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में विफल रहा। विद्वत अधिवक्ता ने हालांकि स्वीकार किया कि गरीब रोगियों के साथ डॉक्टरों की बातचीत के कारण सरकारी अस्पतालों में प्राप्त कार्य अनुभव निजी अस्पतालों से अलग था और वे न्यूनतम बुनियादी ढांचे के साथ काम करने के आदी थे, फिर भी उन्होंने तर्क दिया कि बिहार सरकार के अस्पतालों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं ने राज्य के अन्य गैर-अनियमित निजी अस्पतालों की तुलना में कोई विशेष अनुभव प्रदान नहीं किया और यह कि दोनों श्रेणियों के लिए कोई सार्वजनिक उद्देश्य पूरा नहीं किया गया था, इसी तरह कम वेतन के बदले में रोगियों के झुंड को चिकित्सा उपचार दिया गया।

11. अपीलार्थी के वकील ने आगे नियमावली के नियम 5 और 6 (iii) पर आधारित अपना तर्क दिया कि किसी भी असंवैधानिकता से बचने के लिए केंद्र सरकार और अन्य सार्वजनिक निकायों द्वारा संचालित बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों को

शामिल करने के लिए इसका निर्वचन किया जाना चाहिए।यह तर्क दिया गया था कि नियमावली के नियम 2 (ए) के तहत 'सरकारी' की परिभाषा 'सरकारी अस्पताल' शब्द के अर्थ को नियंत्रित नहीं करती है क्योंकि 'सरकारी अस्पताल' के उपसर्ग के रूप में 'किसी' की उपस्थिति इस तथ्य का संकेत है कि नियमावली में इसके दायरे में सभी सरकारी अस्पतालों की परिकल्पना की गई है। उन्होंने नियमावली में निहित परिभाषा खंड का उल्लेख किया, जो नीचे उद्धृत किया गया हैः

> 2. परिभाषाएं। इस नियम में, जब तक कि संदर्भ में कुछ और अपेक्षित न होः
>
> (क) 'सरकार' से बिहार सरकार अभिप्रेत है.
>
> xxxxxxxxxxxxx"
>
> (जोर दिया गया)

12. यह भी आग्रह किया गया कि बिहार दंत चिकित्सक सेवा नियम, 2014 के अंग्रेजी संस्करण की तुलना में हिंदी संस्करण के उत्थान के संबंध में उच्च न्यायालय का अवलोकन वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि वर्तमान मुद्दा एक अलग अधिनियमिति से संबंधित है जिसका संस्करणों के बीच कोई विरोध नहीं है। अपीलार्थी ने कहा कि दंत चिकित्सक नियमों के अंग्रेजी संस्करण का संदर्भ, जिसमें स्पष्ट रूप से 'सरकारी अस्पताल' को बिहार सरकार और केंद्र सरकार के अस्पताल दोनों के रूप में परिभाषित किया गया है, केवल एक तर्क का समर्थन करने के लिए उदाहरण है कि 'सरकारी अस्पताल' का 'सरकार' से अलग अर्थ हो सकता है और इस प्रकार उसके मामले को इस आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए था।

13. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के विद्वत वकील ने अपीलकर्ता की चुनौती की धारणीयता पर सवाल उठाया और आग्रह किया कि एक बार किसी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के बाद, वह/वह केवल चयन में विफल होने के कारण बाद के चरण में इसकी शुद्धता को चुनौती नहीं दे सकता। यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी सफलता पर 'दो अवसर' ले रही थी, और उसकी चुनौती का अवसरवादी होने के कारण विरोध

किया गया था। इसके अलावा यह प्रत्यर्थियों द्वारा तर्क दिया गया था कि दंत चिकित्सक नियमों से निष्कर्ष निकालने के अपीलकर्ता के प्रयास को उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है.इसके अलावा, विज्ञापन को केवल यह स्पष्ट करने के लिए दिखाया गया था कि केवल बिहार सरकार के अस्पतालों में कार्य अनुभव के लिए अंक दिए जाएंगे।

14. इसके अतिरिक्त, आयोग ने इस अभिवचन के साथ अन्य प्रत्यर्थियों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के अनुपूरक के रूप में एक अलग जवाबी हलफनामा दायर किया है कि न्यायालयों को नियोक्ता द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि यह स्पष्ट रूप से अवैध न पाया जाए। आयोग द्वारा यह आग्रह किया गया है कि खंडपीठ ने नियमावली के नियम 2 (ए) के आलोक में 'सरकारी अस्पताल' शब्द के अर्थ और दायरे की सही व्याख्या की, जो 'सरकार' को बिहार सरकार के रूप में परिभाषित करता है, और इसलिए फैसला सुनाया कि विज्ञापन विषय नियमावली के अनुसार है।

निष्कर्ष और विश्लेषण

15. आरंभ में हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि वर्तमान मामले में हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि नियमावली के दोनों संस्करणों में समान रूप से शब्द हैं। इस प्रकार हम इस धारणा के साथ आगे बढ़ते हैं कि किसी भी टकराव की स्थिति में हिंदी अंग्रेजी संस्करण पर हावी होगी।

प्रारंभिक मुद्दे

16. इसके अतिरिक्त, अंतर्वलित विधिक मुद्दों का विश्लेषण आरंभ करने से पूर्व, प्रारंभिक मुद्दे का समाधान करना आवश्यक है के रखरखाव की क्षमता अपीलार्थी द्वारा दी गई चुनौती की पोष्णीयता पर इस आधार पर सवाल उठाया गया है कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने के कारण वह केवल चयन में विफलता के कारण बाद में इसे

चुनौती नहीं दे सकती है.प्रत्यर्थियों के वकील ने अपनी आपत्ति को साबित करने के लिए इस न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला पर भरोसा किया।

17. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि विबंध का सिद्धांत एक उम्मीदवार को असफल होने के बाद चयन प्रक्रिया को चुनौती देने से रोकता है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा मनीष कुमार शाही बनाम बिहार राज्य के मामले सहित कई निर्णयों में निम्नलिखित विचार व्यक्त करते हुए दोहराया गया हैः

> "16. हम उच्च न्यायालय से भी सहमत हैं कि पूरी तरह से अच्छी तरह से जानते हुए चयन की प्रक्रिया में भाग लेने के बाद कि 19% से अधिक अंक मौखिक परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए हैं, अपीलकर्ता चयन के मानदंड या प्रक्रिया को चुनौती देने का हकदार नहीं है। निश्चित रूप से, यदि अपीलार्थी का नाम योग्यता सूची में आ गया होता, तो उसने चयन को चुनौती देने का सपना भी नहीं देखा होता। अपीलकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया, जब उसने पाया कि उसका नाम आयोग द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में नहीं है। अपीलार्थी का यह आचरण उसे चयन पर सवाल उठाने से स्पष्ट रूप से वंचित करता है और उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार करने से इनकार करके कोई त्रुटियां नहीं की।"

इस सिद्धांत का अंतर्निहित उद्देश्य उम्मीदवारों को एक और प्रयास करने से रोकना और एक गतिरोध से बचना है जिसमें प्रत्येक असंतुष्ट उम्मीदवार, चयन में विफल होने के बाद, दूसरा अवसर पाने की आशा में इसे चुनौती देता है।

18. तथापि, हमें जहां तक चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सहमत होकर अभ्यर्थी द्वारा केवल विहित प्रक्रिया को स्वीकार करके इस सिद्धांत से विभेद करना चाहिए न कि इसकी अवैधता।ऐसी स्थिति में जहां कोई उम्मीदवार वैधानिक नियमों के गलत निर्माण और उससे उत्पन्न होने वाले परिणामों में भेदभाव का आरोप लगाता है,

उसे केवल इसलिए माफ नहीं किया जा सकता है क्योंकि किसी उम्मीदवार ने इसमें भाग लिया है। संवैधानिक योजना पवित्र है और इसका उल्लंघन किसी भी तरह से अननुमेय है।वास्तव में, एक उम्मीदवार को संविधान के प्रावधानों की असाध्य अवैधता या अल्पीकरण पर हमला करने का अधिकार नहीं हो सकता है, जब तक कि वह चयन प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है।

19. सरकारी अस्पतालों में 'कार्य अनुभव' को महत्व देने की अनुमति का प्रश्न भी इस मामले में विवाद की जड़ नहीं है। चिकित्सा एक अनुप्रयुक्त विज्ञान होने के नाते केवल अकादमिक ज्ञान से ही इसमें महारत हासिल नहीं की जा सकती।किसी उम्मीदवार का लंबा अनुभव उसके ज्ञान और विशेषज्ञता को बढ़ाता है।इसी तरह, सरकारी अस्पताल निजी अस्पतालों से काफी अलग हैं क्योंकि पहले वाले अस्पतालों में बुनियादी ढांचे की अनूठी बाधाएं होती हैं और वे गरीब जनता से निपटते हैं। ऐसे गैर-मामूली निजी अस्पतालों में डॉक्टर बहुत कम वेतन के बदले में मरीजों के झुंड को चिकित्सा उपचार देकर सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। इसलिए, जब कार्य अनुभव की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है, तो इस पर कोई विवाद नहीं होता है कि सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों को अलग-अलग वर्गों के रूप में मान्यता है। इसके बजाय इस तरह की मान्यता यह सुनिश्चित करती है कि बिहार जैसे पिछड़े समृद्ध राज्यों में भर्ती किए गए डॉक्टरों को उन क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़े।

20. इस प्रकार अपीलार्थी ने चयन प्रक्रिया को उचित रूप से चुनौती नहीं दी है, लेकिन योग्यता निर्धारण के हिस्से के रूप में केवल प्रत्यर्थियों द्वारा 'कार्य अनुभव' की व्याख्या के खिलाफ अपने दावे को संकुचित कर दिया है। चूंकि किसी कानून या नियम की व्याख्या करना न्यायालयों का अनन्य अधिकार क्षेत्र है और ऐसे मानदंडों को रेखांकित करने में न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश को देखते हुए, अपीलकर्ता की चुनौती को दहलीज पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। तथापि, हम विशेष रूप से अपीलार्थी के मामले की योग्यता पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं और हमारा निश्चय चयन

प्रक्रिया के परिणाम से भिन्न है।यह संभव है कि उसके बाद जो कुछ भी हो, उसके बाद उसका चयन हो या नहीं हो।

सांविधिक व्याख्या

21. यह सांविधिक व्याख्या की एक निश्चित तोप है कि पहले कदम के रूप में, न्यायालयों को उपबंध के पाठ की व्याख्या करनी चाहिए और इसे शाब्दिक रूप से तैयार करना चाहिए।किसी कानून के प्रावधानों को उनके मूल व्याकरणिक अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए ताकि उनके शब्दों का अर्थ एक समान हो सके।तथापि, व्याख्या के इस उपकरण को केवल उन मामलों में लागू किया जा सकता है जहां अधिनियमिति का पाठ केवल एक अर्थ के लिए अतिसंवेदनशील है। तथापि, ऐसी स्थिति में जहां 13 पाठ के अर्थ में अस्पष्टता है, न्यायालयों को भी ली गई व्याख्या के परिणामों पर उचित ध्यान देना चाहिए।

22. न्यायालयों की यह जिम्मेदारी है कि वे पाठ की इस तरह से व्याख्या करें जो कठिनाई, असुविधा, अन्याय, बेतुकी या विसंगति के किसी भी तत्व को दूर करे। सांविधिक अर्थान्वयन का यह सिद्धांत मॉडर्न स्कूल बनाम भारत संघ के मामले में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया। यह दोहराते हुए कि कानून को अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाना चाहिए और प्रणाली में कोई भ्रम या टकराव पैदा नहीं करना चाहिए। यदि ऐसी विधि के पाठ का सामान्य अर्थ उन उद्देश्यों के लिए अनुकूल नहीं है जिन्हें प्राप्त किया जाना है, तो ऐसी कमी को दूर करने के लिए उसका तदनुसार व्याख्या किया जाना चाहिए।

23. इसमें कोई संदेह नहीं है कि विज्ञापन जैसे कार्यकारी कार्य न तो कानूनों के दायरे का विस्तार कर सकते हैं और न ही उन्हें सीमित कर सकते हैं। इसलिए नियमावली में 'सरकारी अस्पताल' वाक्यांश की व्याख्या पर विचार करना आवश्यक है। हमारे सामने दो व्याख्याएं रखी गई हैं जिनका सारांश इस प्रकार हैः

क. केवल बिहार सरकार द्वारा संचालित अस्पताल

ख. बिहार सरकार या उसके उपकरणों द्वारा संचालित अस्पतालों के साथ-साथ बिहार के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी अन्य गैर-असंगठित निजी अस्पताल। प्रत्यर्थियों द्वारा दी गई इस शब्द की पूर्व व्याख्या,

एक संकीर्ण वर्ग बनाता है जबकि अपीलकर्ता द्वारा की गई बाद की व्याख्या व्यापक और अधिक समावेशी है।

शाब्दिक व्याख्या

24. प्रारंभ में, प्रत्यर्थियों का यह तर्क कि 'सरकारी अस्पताल' शब्द का अर्थ नियमावली के नियम 2 (क) के अधीन 'सरकार' की प्रतिबंधात्मक परिभाषा से आबद्ध होगा, ठीक नहीं लगता है।यह तय किया गया है कि व्याकरणिक नियमों को वैधानिक व्याख्या के दौरान उचित महत्व दिया जाना चाहिए। नियम 2 एक परिभाषा संबंधी प्रावधान है और सरकार को संज्ञा के रूप में परिभाषित करता है। हालांकि, यह आवश्यक नहीं है कि यह उन उदाहरणों को नियंत्रित करेगा जहां शब्द का उपयोग दूसरे रूप में किया गया है। नियम 5 के तहत, क्रियात्मक वाक्यांश 'कोई भी सरकारी अस्पताल' है। यहां 'सरकार' कुछ संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले लोगों को बाहर करने के लिए संज्ञा 'अस्पताल' को सीमित रूप से परिभाषित कर रही है। इस प्रकार, 'सरकारी अस्पताल' के हिस्से के रूप में 'सरकार' एक संज्ञा है और इसे एक विशेषण के रूप में उपयोग किया गया है। संज्ञा के विशेषण रूप में इस तरह के उपयोग से उसका चरित्र पूरी तरह बदल जाता है और इसके संज्ञा रूप का अर्थ निकालना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा। यह विशेष रूप से इस बात पर विचार करते हुए सही है कि कैसे नियम 2 के प्रारंभिक भाग में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि इसके तहत निर्धारित परिभाषाओं का संदर्भ दिया जाएगा जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो। इसलिए 'सरकारी अस्पताल' वाक्यांश का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि इसमें अन्य गैर-निजी अस्पतालों को शामिल नहीं किया गया है, जो अन्यथा विशेष रूप से सरकार की मदद और सहयोग से चलाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, सामान्य उपयोग में अंतर को देखते हुए, जिसमें 'सरकारी अस्पताल' सभी गैर-मामूली निजी

अस्पतालों को संदर्भित करता है और न कि किसी विशेष सरकार द्वारा स्थापित अस्पतालों को, नियम 5 और 6 (iii) नियम 2 (क) द्वारा बाध्य नहीं होगा।

25. नियम 5 में 'कोई' शब्द की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण है। यह कार्य अनुभव के उपार्जन के लिए पात्र अस्पतालों को व्यापक अर्थ प्रदान करने के विधायी आशय को इंगित करता है। इसलिए नियम 2 (क) की प्रतिबंधात्मक परिभाषा को लागू करने से उसी अंतर्निहित संज्ञा के लिए व्यापक और प्रतिबंधात्मक विशेषणों को लागू करने में एक विषम स्थिति पैदा होगी।नतीजतन, हम इस वाक्यांश की एक व्यापक व्याख्या को अपनाने के लिए प्रवृत्त हैं, और नियम 2 (ए) पर जोर नहीं देते हैं, जैसा कि प्रत्यर्थियों द्वारा आग्रह किया गया है।

26. इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थियों के व्याख्या को अपनाने से अनिश्चितता बढ़ेगी और व्यावहारिक कठिनाइयां पैदा होंगी।जब नियम 2 (क) को 'सरकारी अस्पताल' के लिए लागू किया जाता है तो इस बारे में पर्याप्त अस्पष्टता पैदा हो जाती है कि क्या सरकार के उपकरणों द्वारा संचालित अस्पताल, जो बिहार सरकार के स्वामित्व में सख्त रुप से नहीं हैं, को नियम 5 के तहत शामिल किया जाएगा या नहीं। जब प्रत्यर्थियों के विद्वत वकील से यह प्रश्न पूछा गया कि क्या नगर पालिका द्वारा स्थापित अस्पताल या राज्य के धन से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित संस्थान द्वारा संचालित अस्पताल को उनकी परिभाषा में शामिल किया जाएगा, तो कोई स्पष्ट उत्तर सामने नहीं आया। किसी भी चयन प्रक्रिया में इस तरह के मुद्दे बार-बार उठने स्वाभाविक हैं। यह देखते हुए कि ऐसे प्रश्नों का कोई सरल उत्तर नहीं है, सरकार द्वारा अपनाई गई कठोर व्याख्या प्रणाली में टकराव पैदा करेगी और व्याख्यात्मक अराजकता का कारण बनेगी जो सार्वजनिक रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा करने के स्पष्ट और उचित अधिकार को कमजोर करेगी।

27. इसके अतिरिक्त, यदि किसी ऐसे विकल्प के बीच सामना करना पड़े जिसमें केवल कुछ ही लोग पात्र होंगे बनाम एक काफी बड़ा समूह होगा, तो हम महसूस करते हैं कि आवेदकों का एक विविध समूह होने के लिए बाद वाले समूह को अपनाया जाना चाहिए। यह योग्यता को बढ़ावा देगा, बेहतर डॉक्टर लाएगा और जनता को

सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर प्रदान करने की संवैधानिक योजना को आगे बढ़ाएगा। इस प्रकार हमारा विचार है कि मामले में नियमावली के प्रावधानों का शाब्दिक विश्लेषण के सिद्धांत को लागू करके न तो अर्थ लगाया जा सकता है और न ही व्याख्या की जा सकती है।

उद्देश्यपूर्ण व्याख्या

28. उपर्युक्त विश्लेषण के अनुसरण में, हमारा यह मत है कि इसके उद्देश्यों के आलोक में नियमों के उपबंधों की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या करना आवश्यक है। अन्यथा भी, अनुच्छेद 309 के पूर्ववर्ती भाग के अनुसार, उसके अधीन बनाए गए नियमावली सभी अन्य संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप होने चाहिए, जिसमें आवश्यक रूप से भाग III शामिल है। सरकारी अस्पतालों में भर्ती से संबंधित, यह स्पष्ट है कि नियमावली का विषय और उद्देश्य अनुच्छेद 16 की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए।

29. इसके अतिरिक्त, 'सरकारी अस्पताल' की अभिव्यक्त परिभाषा के अभाव को देखते हुए नियमालवी के तहत, जो इस बहस का केंद्रीय मुकाम है, हम संवैधानिक मूल्यों का वैधानिक व्याख्या के एक साधन के रूप में उपयोग करना उचित समझते हैं। यह सर्वविदित है कि संविधान को न केवल विधानों की वैधता का परीक्षण करने के लिए एक मानक के रूप में देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे राज्य की कार्रवाई का मार्गदर्शन करने के लिए एक प्रेरणादायक दस्तावेज के रूप में भी देखा जाना चाहिए। जब दो तर्कसंगत व्याख्याएं हों तो संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली व्याख्या को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

30. हमारी संवैधानिक योजना के तहत, राज्य के दायित्वों और कर्तव्यों को तीन स्तरीय शासन प्रणाली का उपयोग करते हुए स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार, राज्य स्तर पर व्यक्तिगत राज्य सरकारें और स्थानीय स्तर पर विभिन्न नगरपालिकाएं/पंचायतें आम जनता के कल्याण के लिए अपने-अपने संवैधानिक कर्तव्यों का समानांतर रूप से निर्वहन करती हैं।

31. संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, पर्याप्त पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्यों का सम्मान करते हुए केंद्र और राज्य सरकारें दोनों विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं तैयार करती हैं और अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित संस्थानों की स्थापना करती हैं। इसके अलावा, संविधान की अनुसूची 11 की प्रविष्टि 23 के साथ पठित अनुच्छेद 243 जी के तहत, राज्य का विधानमंडल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और डिस्पेंसरी सहित स्वास्थ्य और स्वच्छता के कार्यों को पंचायती राज संस्थाओं को सौंप सकता है। इसी प्रकार, राज्य विधानमंडल अनुसूची 12 की प्रविष्टि 6 के साथ पठित अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य नगरपालिकाओं को सौंप सकती है। इन स्थानीय सरकारों के अस्पतालों को अक्सर राज्यों के समेकित कोष से प्राप्त धन के आधार पर चलाया जाता है।इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि संविधान में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थानों सहित कई विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अस्पतालों की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

32. इसके अतिरिक्त, यह सर्वविदित तथ्य है कि गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश भर में केन्द्र या राज्य सरकारों, विशेषकर कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों के परिकरणों द्वारा अनेक अस्पताल स्थापित किए गए हैं।अतः यह अस्पताल सभी उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए अन्य सरकारी अस्पतालों के समतुल्य हैं और ऐसे अस्पतालों में चिकित्सक द्वारा प्राप्त अनुभव बिहार सरकार द्वारा स्थापित अस्पताल में अर्जित विशेषताओं को समाहित करता है।

33. अन्य अस्पतालों भी भाग 4 के तहत संवैधानिक दायित्वों के अनुसरण में राज्यों और केन्द्र के उपकरणों द्वारा स्थापित किए गए हैं। यद्यपि ये प्रतिवादियों द्वारा प्रतिपादित नियमावली के दायरे में सख्त रुप से आच्छादित नहीं है तो भी ये आम जनता को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करे ना के समाज प्रयोजन में संलग्न है।

इसका एक उपयुक्त उदाहरण सेना के अस्पतालों का है और ऐसे अस्पतालों से प्राप्त अनुभवों की अनदेखी करने और नकारने का कोई कारण नहीं है।

34. अतः यह आग्रह करना अतार्किक है कि ऐसे किसी अस्पताल में कार्य अनुभव बिहार सरकार के अस्पताल से भिन्न है। इसलिए पंचायतों या नगरपालिकाओं या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित इन अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा प्राप्त अनुभव और बिहार सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों के बीच अंतर करना संवैधानिक रूप से अन्यायपूर्ण होगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार या नगरपालिकाओं/पंचायती राज संस्थानों द्वारा संचालित अस्पतालों के बीच भेदभाव करने का कोई भी प्रयास हमारे संवैधानिक शासन के ढांचे को प्रभावित करने के लिए बाध्य है।

35. ऐसा कहने के बाद, हम इस तथ्य से अनजान नहीं हैं कि समानता का अर्थ यह नहीं है कि कोई वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय, कभी-कभी असमान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार करना आवश्यक हो सकता है क्योंकि असमान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार एक अन्यायपूर्ण स्थिति पैदा करता है। हालांकि, इस तरह का वर्गीकरण मनमाना नहीं होना चाहिए, लेकिन तर्कसंगत रूप से कुछ गुणवत्ता या विशेषताओं पर आधारित होना चाहिए जो इस प्रकार बनाए गए लोगों के वर्ग के भीतर पहचाने जा सकते हैं और ऐसे वर्गीकरण से बाहर रखे गए लोगों में अनुपस्थित हैं।

36. हमारा विचार है कि नियमावली बनाने के पीछे का उद्देश्य बिहार के अस्पतालों की अनूठी चुनौतियों को पहचानना और गैर-मामूली निजी अस्पतालों में काम करने के लिए डॉक्टरों को प्रोत्साहित करना था।प्रत्यर्थियों के विद्वत वकील की प्रस्तुति में कुछ तथ्य है कि बिहार मुख्य रूप से गरीब है और इस प्रकार निजी अस्पतालों में उनके समकक्षों की तुलना में डॉक्टरों को ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण की आवश्यकता है.गैर-निजी अस्पताल में अनुभव अपने डॉक्टरों में संवेदनशीलता पैदा करता है, जिससे वे गरीब रोगियों की पीड़ा को समझने में अधिक निपुण हो जाते हैं। इस तरह का अनुभव निःसंदेह सरकारी अस्पतालों के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में उपयोगी होगा और उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करते समय इसे उचित महत्व दिया

जाना चाहिए।इस प्रकार बिहार सरकार के अधीन काम करने वाले व्यक्तियों के केवल एक छोटे वर्ग को शामिल करने के लिए सरकारी अस्पतालों की व्याख्या करना स्पष्ट रूप से गलत और गैर-लाभकारी है।इस तरह के उद्देश्य को नियमावली की समझ से विफल नहीं किया जा सकता है जैसा कि हमने व्याख्या की है।

निष्कर्ष

37. उपर्युक्त कारणों से, अपील की अनुमति दी जाती है।बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम, 2013 के नियम 5 और 6 (iii) का यह अर्थ लगाया जाता है कि बिहार सरकार या उसके इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा संचालित किसी भी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा प्राप्त अनुभव के साथ-साथ बिहार के क्षेत्र के भीतर किसी भी अन्य गैर-निजी अस्पताल (केंद्र सरकार, नगरपालिकाओं और पंचायती राज संस्थानों द्वारा संचालित या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा संचालित) को भी इसमें शामिल किया गया है। तदनुसार, प्रत्यर्थियों को दो महीने के भीतर अपीलकर्ता और इसी तरह के अन्य उम्मीदवारों को उचित महत्व देकर एक नई मेधा सूची तैयार करने का निर्देश दिया जाता है। हालांकि, हम स्पष्ट करते हैं कि कार्य अनुभव के आधार पर भारांक देने से उम्मीदवार की उपयुक्तता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(दीपक गुप्ता), न्यायमूर्ति

(सूर्यकांत), न्यायमूर्ति

नई दिल्ली

दिनांकः17 दिसंबर 2019

खण्डन (डिस्क्लेमर) :– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।